Additional Irrigation Potential in various Districts of Gujarat

6693. SHRI GOPALSINH G. SO-LANKI: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state

(a) the total amount of outlay fixed for 1993.94, 1994-95 and 1995-96 to create additional irrigation potentiality through different sources in Gujarat particularly for Ahmedaad. Baroda, Surat, Bharueh and Panch Mahal districts;

(b) whether the amount allocated for this purpose has been thereof: and

(c) if so the details thereof; and

(d) if not, the reasons thereof?

THE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) to (c) The Ministry of Water Resources collects and maintains data on physical and financial parameters on irrigation, only at the State level. Allocation of funds to 'Major & medium' projects and Minor Irrigation schemes is included in the overall central assistance in the State Plan approved by the Planning Commission . Anticipated expenditure for 1993-94 and approved outlays for 1994-95 for "Major & Medium' projects and Minor irrigation schemes in Gujarat are as under:—

(Rs. in crores)

Sector	Anticipated Expenditure (1993-94)	Approved Outlays (1994-95)
Major & medium projects	440.68	485.98
Minor irrigation schemes	59.87	100.00
TOTAL :	500.55	585.98

In addition institutional investment for Minor irrigation schemes during 1993-94 was Rs. 31.75 crores. A target of Rs. 77.00 crores was fixed for 1994-96. The Annual Plan (1995-96) proposals for the State of Gujarat are yet to come up for discussion in the Planning Commission.

(d) Does not arise.

गुजरात को और बकाया राशि

6694. श्री कनकसिंह मोहनसिंह भंगरौला : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरदार सरोवर परियोजना में शामिल राज्यों, अर्थात मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान द्वारा गुजरात सरकार को दी जाने वाली लागत की राशि का कोई हिस्सा बकाया रह गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगया नायडू) : (क) और (ख) सरदार सरोवर परियोजना के संबंध में 31-3-1995 की स्थिति के अनुसार

गुजरात सरकार को पक्षकार राज्यों से देय हिस्से का ब्यौरा इस प्रकार है :

मध्य प्रदेश	295.85 करोड़ रुपए
महाराष्ट्र	35.24 करोड़ रुपए
राजस्थान	132.17 करोड़ रुपए
कुल	463.26 करोड़ रुपए

(ग) गुजरात सरकार को अन्य पक्षकार राज्यों द्वारा सरदार सरोवर परियोजना को अंशलागत के भुगतान संबंधी मुद्दे पर नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण और सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति की बैठकों में विचार विमर्श किया गया है और गुजरात सरकार की बकाया देयों का तत्काल निपटान किए जाने की आवश्यकता के बारे में राज्यों को अवगत कर दिया गया है । इस मुद्दे पर नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की पुनरीक्षा समिति में भी विचार किया गया है जहां बकाया वाले राज्य गुजरात के साथ द्विपक्षीय बैठकों के जरिए मुद्दे को हल करने के लिए सहमत हुए हैं ।

बिहार में नहरों का निर्माण

6695. **श्री आरू मोहम्मद:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में नहरें बनाने की कोई योजना बनाई है और नहरों के निर्माण हेतु केन्द्रीय स्तर पर कोई सहायता प्रदान की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है और गत दो वर्षों के दौरान सहायता के रूप में कितनी धनराशि प्रदान की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) इस समय, बिहार में 19 वृहद और 29 मझौली सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं जिनमें नहरों का निर्माण भी शामिल है । एक वृहद परियोजना नामश: सुवर्णरेखा बहु प्रयोजनी परियोजना का कार्यान्वयन विश्व बैंक की सहायता से 1989 तक किया जा रहा था । वर्तमान नीति के अनुसार, सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, प्रतिपादन, वित्तपोषण और कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है । केन्द्रीय सहायता एक मुश्त ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है जो विकास के किसी विशेष क्षेत्र अथवा परियोजना से जुड़ी नहीं होती है ।

(ख) और (ग) निर्माणाधीन परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं । विश्व बैंक की सहायता से चल रही राष्ट्रीय जल प्रबन्ध परियोजना के अन्तर्गत हयुवा ब्रांच नहर एवं डुमेरी ब्रांच नहर के नवीकरण और सुवर्णरेखा परियोजना के चरण–II के लिए परियोजना प्रस्ताव तैयार करने के लिए 1993–94 और 1994–95 के दौरान क्रमश: 357.49 लाख रुपए और 166.27 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति की गयी । इसके अतिरिक्त डॉन ब्रांच नहर के नवीकरण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान अनुदान सहायता के रूप में 173 लाख रुपए नियुक्त किए गए ।

Agreement between India and Nepal on Tanakpur Hydel Project

6696. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Central Government have agreed to examine the proposals made by Nepal on the issue of Tanakpur Hydel Project; and

(b) if go, the details (hereof?